(i) Need for stopping illegal felling of trees in Bihar

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम पेड़-पौधों की रक्षा, नये पेड़ लगाने और वायु-मंडल प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए अनेक उपाय कर रहे हैं। प्रधान मंत्री जी ने भी वृक्ष के महत्व, वृक्ष और मानव जीवन के सम्बन्ध, वृक्षों की आर्थिक उपयोगिता और वर्षा से उनके गहरे सम्बन्ध की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। इस स्थिति में मैं सदन का ध्यान बिहार में रांची क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

किसी समय रांची बहुमूल्य वन-संपदा के लिये सारे देश में विख्यात था। लेकिन गत 15 वर्षों में वहां वन-सम्पत्ति बुरी तरह नष्ट हो गई है। मैं हाल ही का चर्चा करती हूं। जनवरी से दिसम्बर, 1982 तक की अवधि में गैर-कानूनी ढंग से काटी गई इमारती लकड़ी से भरे 132 ट्रक जब्त किये गये थे। इसकी कीमत लगभग 13 लाख रुपये है। इमारती लकड़ी के व्यापारी आदिवासियों की निर्धनता का लाभ उठा कर पाँच या दस रुपये प्रति-पेड़ उनसे खरीद लेते हैं और वन-विभाग से रसीद ले कर उसे अन्य स्थानों पर भेज देते हैं। इसके लिए हमारा वन अधिनियम (फारेस्ट एक्ट) भी उत्तरदायी है। गैर-कानूनी ढंग से वृक्षों के काटने पर केवल 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। पिछले वर्ष तीन हजार एक सौ सड़सठ (3,167) ट्रक इमारती लकड़ी रांची पहुंची। मेरा अनुमान हैं कि छः हजार ट्रक इमारती लकड़ी विभिन्न व्यापारियों के स्टाक में मौजूद है। झारखंड पार्टी के मंत्री ने इस विषय की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधान मंत्री जी को पत्र भी लिखा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आदिवासियों का शोषण रोकने और पेड़ों की रक्षा के लिये तुरन्त कदम उठाए जाएं।

(ii) Need to Solve the problem of unemployment of the youth.

SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL (Kota) : Sir, more than 50,000 youths have collected today in Delhi and are marching towards Parliament to meet you so as to explain to you their sufferings, grievances and pressing demands. In a democratic set-up, what place better than Parliament can there be for the people to air their grievances and who can be a better person that the Speaker of Lok Sabha in whom they should repose their confidence for doing the needful.

Unemployment and poverty are the two faces of the same coin. Today more than 4 crores of young men and women are estimated as unemployed in the country and this number is growing faster. 5 million persons join the job market every year and by the turn of the century this will mean a net addition of 120 million job seekers. This is the future staring in their face.

The more outstanding demands of the youth are :

(i) Right to work be included as a fundamental right in the Constitution and it be enforced according to a time-bound programme ;

(ii) "The National Employment Programme" should be formulated and placed before Parliament ;

(iii) Immediate review of the national system be undertaken and suitable changes be made to make it job-creative ; and

(iv) Employment Guarantee Scheme should be launched in all the States of the country covering the educated unemployed also.

To stem the rising frustration in the youth on account of gigantic dimensions of unemployment, it is imperative that a National Employment Programme be formulated by the Government.

When an Employment Guarantee Scheme can be launched and worked out in Maharashtra, there is no reason why it cannot be followed in other States also.